

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक वि.प्र./पीपीपी/पीएचसी /2017/ 44

दिनांक 28/8/17

आदेश

याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय के एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6161/2017 के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 27.04.2017 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के माध्यम से निदेशालय को प्राप्त हुआ।

एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 6161/2017 माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में याचिकाकर्ता सरजीत प्रसाद गुर्जर पुत्र श्री रामप्रसाद गुर्जर, शकुंतला चौधरी श्री श्री चतुर्भुज चौधरी, सीताराम हरिजन पुत्र श्री कालुराम हरिजन, लक्ष्मी सैनी पुत्री श्री रामदेव सैनी, सोनू वर्मा पत्नी श्री रामदयाल शर्मा, मन्जु चौधरी पुत्री श्री बैजनाथ चौधरी, लक्ष्मी सैनी पुत्री श्री घनश्याम सैनी, सुरज देवी शर्मा पत्नी श्री श्याम सुन्दर शर्मा, सोनू वर्मा पत्नी श्री रामदेव गुर्जर एवं लोकेश सेन पुत्री श्री बाबुलाल सेन द्वारा याचिका दर्ज की गई, जिसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 27.04.2017 को निम्नानुसार आदेश दिया गया।

"In case, a representation is so addressed within the aforesaid period, the State-respondents are directed to consider and decide the same by a reasoned and speaking order as expeditiously as possible in accordance with law. However, in no case later than two months from the date of receipt of the representation along with a certified copy of this order."

उक्त आदेश के संबंध में सरजीत, शोभा सैनी, लक्ष्मी सैनी, मादुल देवी एवं लोकेश सेन के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक को अभ्यावेदन दिया गया।

याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन में यह दिया गया है कि हम सभी प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा पी.एच.सी. गनैती एवं सम्बद्ध उपकेन्द्र जिला-टोंक पर नियुक्त हुए हैं, जो एक निर्भर कार्य से नियमित एवं सतोषपर्द कार्य एवं सेवायें प्रदान कर रहे हैं, लेकिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के आदेश क्रमांक 1399 दिनांक 06.04.2017 के द्वारा सभी प्लेसमेंट एजेंसी का अनुबंध पत्र निरस्त करने का पत्र प्राप्त होने पर हम सभी ने उक्त आदेश के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर में रिट पिटिशन संख्या 6161/2017 पेश की गई। जिसके संबंध में माननीय न्यायालय ने दिनांक 27.04.2017 को हम सभी को हमारे कार्य से न हटाकर हमारी सेवा नियमित जारी करने के आदेश प्रदान किया है।

उक्त अभ्यावेदन एवं माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के आदेश दिनांक 27.04.2017 का अध्ययन किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गनैती (टोंक) को अनुबंध/समाप्त दिनांक 16.05.2016 के द्वारा डॉ० एस.पी.सुदारनिया सेवाप्रदाता को निजी जनसहभागिता से संचालन हेतु दिया गया था। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर याचिकाकर्ताओं/कामिकों का सेवाप्रदाता द्वारा नियुक्त किया गया था। सेवाप्रदाता से किये गये अनुबंध के आर.ए.पी. के विन्दु संख्या 4 के उपविन्दु 17 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "सेवाप्रदाता को निर्युक्त कामिकों को राजकीय सेवा में समायोजित/नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।"

याचीगणों का विभाग के साथ प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं किए जाने के कारण एवं विभाग द्वारा डॉ० एस.पी.सुदारनिया के साथ अनुबंध समाप्त/संतोषजनक नहीं पाए जाने के कारण" समाप्त होने से याचीगणों के प्रति कोई उत्तर नहीं है। सेवाप्रदाता के साथ अनुबंध समाप्त होने के बाद उक्त पी.एच.सी में पूर्व की भांति विभाग के नियमित कर्मचारियों का पदस्थापन किया जाकर पी.एच.सी के कार्य को चलाया जा रहा है। उक्त पी.एच.सी पर याचीगणों के स्थान पर अन्य संविदा कर्मियों को नियुक्ति/पदस्थापन नहीं की गई है।

माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में दायर सिविल रिट पिटिशन में याचिकाकर्ताओं द्वारा तथ्य को सही ढंग से पेश नहीं किया गया है कि उक्त कर्मिकों को राज्य सरकार द्वारा ग्लेसनेट एजेंसी से नहीं लगाया गया तथा उक्त पी.एच.सी को संचालन में रखने के लिए सेवाप्रदाता डॉ०एस०पी०सुदारनिया द्वारा लगाया गया अनुबंध समाप्त दिनांक के नियम एवं शर्तों के अनुसार सेवाप्रदाता द्वारा लगाये कामिकों के प्रति राज्य सरकार का सेवा में सम्मिलित करने का दायित्व नहीं है।

अतः उक्त तथ्यों के परिपेक्ष में याचीगणों के अभ्यावेदन का आजीकार किया जाता है।

निदेशक (जन स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

दिनांक: 28.8.17

क्रमांक: चि.प्र./पीपीपी/पीएचसी /2017/ 441

प्रतिवेदन निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा०) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोक।
4. संबंधित याचिकाकर्ता.....।
5. प्रभाषी सर्वर रूम, मुख्यालय।
6. संबंधित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर